ई-न्यूज
24 न्यूज अपडेट
WebSite.: https://24newsupdate.in
उदयपुर, गुरूवार 13 फरवरी 2025
Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com
वर्ष 1 अंक 337

ग्राम पंचायतों के प्रशासकों को नहीं हटा पाएंगे कलेक्टर : सरकार से अनुमति लेनी होगी, उप सरपंच का पद खाली होने पर वार्ड पंच बनेगा प्रशासक



24 न्यूज अपडेट

राज्य सरकार ने कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम पंचायतों में लगाए जाने वाले प्रशासकों को लेकर नया फरमान जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक जिला कलेक्टर्स उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों में प्रशासक तो नियुक्त कर सकेंगे, लेकिन उनको हटाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी।

इस संदर्भ में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। अभी तक इन प्रशासकों को हटाने का अधिकार कलेक्टर्स के पास ही रहता था। आदेश के बाद सरकार ने ये अधिकार कलेक्टर से छीनकर अपने पास रखे हैं।

उप सरपंच का पद खाली होने पर वार्ड पंच बनेगा प्रशासक

अगर किसी ग्राम पंचायत में सरकार जिसे प्रशासक नियुक्त कर रखा है और उसे सरकार हटाती है। उसकी जगह उप सरपंच को लगाया जाएगा। लेकिन ग्राम पंचायत में अगर उप सरपंच का पद खाली है तो सरकार वार्ड पंच में से किसी एक को अपनी इच्छानुसार प्रशासक के तौर पर लगाएगी। इसका प्रस्ताव जिला कलेक्टर के जरिए पंचायतीराज विभाग को भिजवाया जाएगा।

6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुआ

आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुआ है। सरकार ने इन पंचायतों में सरपंचों को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया है। सरकार ने पहली बार प्रशासक के तौर पर जनप्रतिनिधियों को नियुक्त किया है। जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच का पद खाली है, वहां उप सरपंच को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया है।

दलाई लामा को Z कैटेगरी सिक्योरिटी मिली, सुरक्षा मे तैनात रहेंगे इतने सुरक्षाकर्मी



24 न्यूज अपडेट

नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खुफिया जानकारी के आधार पर गुरुवार को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है. इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा खतरे की रिपोर्ट मिलने के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है.

89 वर्षीय दलाई लामा की सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे. इसमें उनके आवास पर सशस्त्र स्टेटिक गार्ड के अलावा 24 घंटे सुरक्षा देने वाले निजी सुरक्षा अधिकारी और शिफ्ट में काम करने वाले सशस्त्र कमांडो शामिल हैं.

कैसी होगी सुरक्षा व्यवस्था!

33 सुरक्षा जवानों में 10 सशस्त्र स्टैटिक गार्ड जो उनके घर पर रहेंगे. वहीं, 6 निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) चौबीस घंटे उनके साथ मौजूद रहेंगे. इसके अलावा 12 कमांडो तीन शिफ्टों में उनकी सुरक्षा में तैना होंगे. साथ ही दो वॉचर्स जो शिफ्ट में निगरानी करेंगे. तीन ट्रेंड ड्राइवर हर समय उनके काफिले में साथ रहेंगे.

कौन हैं बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा!

दलाई लामा का जन्म वर्ष 1935 में ल्हामो थोंडुप के रूप में हुआ था. जब वे दो वर्ष के थे तब उन्हें उनके पूर्ववर्ती तिब्बती धर्मगुरु का पुनर्जन्म माना गया. वहीं वर्ष1940 में उन्हें तिब्बत की राजधानी ल्हासा में 14वें दलाई लामा के रूप में मान्यता प्रदान की गई. 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया. इसके बाद वर्ष 1959 में चीन के खिलाफ एक विद्रोह विफल हो गया, इसके बाद दलाई लामा भारत आ गए. तभी से वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासन में रह रहे हैं. दलाई लामा को अहिंसा और शांति के प्रयासों के लिए वर्ष 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

नेशनल हाईवे पर टोल कलेक्शन को वेरिफाई करने के लिए AI का इस्तेमाल किया जाएगाः नितिन गडकरी



24 न्यूज अपडेट

नई दिल्लीः केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा को बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके गुजरने वाले वाहनों की संख्या और वर्गीकरण की स्वतंत्र रूप से निगरानी करने के लिए हाई-वेल्यू वाले टोल प्लाजा पर ऑडिट कैमरे लगाने पर विचार कर रहा है.

उन्होंने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अत्रैला शिव गुलाम शुल्क प्लाजा की एक घटना का भी जिक्र किया, जहां पूरा कैश वसूला गया था, जिसका कुछ हिस्सा शुल्क प्लाजा के टोल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं बल्कि एक अनधिकृत हैंडहेल्ड मशीन के माध्यम से संसाधित किया गया था. उन्होंने कहा, "इस घटना से सीखते हुए एनएचएआई का लक्ष्य अमान्य/गैर फास्टैग वाहनों से केश कलेक्शन प्रक्रिया को मजबूत करना है और शुल्क प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों की गिनती पर सख्ती से नजर रखने के लिए अतिरिक्त निगरानी पर विचार किया जा रहा है, ताकि टोल प्लाजा पर प्राप्त रसीदों से उसका मिलान किया जा सके."

डीएमके सांसद दयानिधि मारन के सवाल का जवाब

गडकरी डीएमके सांसद दयानिधि मारन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल कलेक्शन से संबंधित धोखाधड़ी से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे. मंत्री ने कहा कि एनएचएआई ने घरौंडा, चोर्यासी, नेमिली, अर्बन एक्सटेंशन रोड (UEI) -II और द्वारका एक्सप्रेसवे पर पांच टोल प्लाजा पर फास्टैग और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान (ANPR) बेस्ड टोल कलेक्शन लागू करने के लिए बिड इंवाइट की हैं.

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन

उन्होंने बताया कि यह सिस्टम सिर्फ फास्टैग के जरिए यूजर्स फीस कलेक्शन को सक्षम बनाता है. अमान्य/गैर-फास्टैग वाहनों के लिए ई-नोटिस प्रस्तावित हैं, जिससे टोल कलेक्शन प्रोसेस से कैश कलेक्शन समाप्त हो जाता है. अपने जवाब में गडकरी ने यह भी कहा कि 98 प्रतिशत से अधिक यूजर्स फीस कलेक्शन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) कार्यक्रम के तहत फास्टैग के माध्यम से होता है. सड़क परिवहन ने कहा कि इस लेन-देन में एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस शामिल है, जिसमें काटी गई यूजर फीस (टोल) की जानकारी राजमार्ग यूजर्स को दी जाती है और इसे एक सेंट्रल रिपॉजिटरी में रिकॉर्ड किया जाता है. इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई भी फास्टैग लेनदेन तीनों हितधारकों - यूजर्स फीस प्लाजा पर अधिग्रहणकर्ता बैंक, एनपीसीआई और जारीकर्ता बैंक की भागीदारी के बिना नहीं हो सकता है.

राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्रदास को जल समाधि

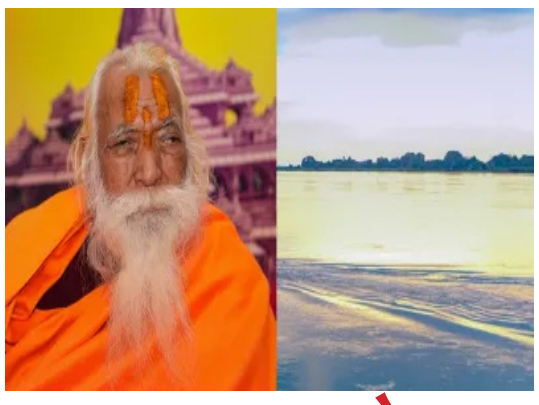

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्रदास को जल समाधि दी गई। उनके पार्थिव शरीर को 25-25 किलो बालू से भरी 4 बोरियों से बांधकर सरयू नदी की बीच धारा में प्रवाहित कर दिया गया। उन्होंने 80 वर्ष की आयु में बुधवार को अंतिम सांस ली थी। पालकी से पार्थिव शरीर लता मंगेशकर चौक होते हुए सरयू घाट लाया गया। उनके शिष्य प्रदीप और विजय भी साथ थे। पहले सरयू नदी में पार्थिव शरीर को स्नान कराया गया। फिर संत तुलसीदास घाट पर जल समाधि दी गई। अंतिम यात्रा से पहले दोपहर 12 बजे पार्थिव शरीर को रथ पर रखा गया। बैंड-बाजे के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर विदाई दी। भारी भीड़ के चलते यात्रा को राम मंदिर के सामने से नहीं निकाला गया। केंद्रीय मंत्री सतीश शर्मा और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने श्रद्धांजलि दी। सरयू घाट पर हजारों श्रद्धालु अंतिम दर्शन के लिए घंटों खड़े रहे। 3 फरवरी को ब्रेन हेमरेज के बाद उन्हें अयोध्या से लखनऊ च्छप् रेफर किया गया था। बुधवार को उन्होंने लखनऊ में अंतिम सांस ली। महत्वपूर्ण संतों और नेताओं की उपस्थिति रही। जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामदिनेशाचार्य, निर्वाणी अनी अखाड़ा के पूर्व श्री महंत धर्मदास, विधायक वेद गुप्ता, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, वशिष्ठ भवन के महंत राघवेश दास की उपस्थित रही।

वक्फ बिल पर JPC रिपोर्ट संसद में पेश, हंगामा



24 न्यूज अपडेट

बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन संसद में वक्फ संशोधित बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश करने को लेकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में BJP सांसद मेधा कुलकर्णी ने तो लोकसभा में JPC चेयरमैन और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने इस रिपोर्ट को पेश किया।

इसे लेकर दोनों सदनों में विपक्ष ने आपत्ति जताई। इनका आरोप है कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को डिलीट कर दिया गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'जेपीसी की यह रिपोर्ट फर्जी है। इसमें विपक्ष की असहमतियों को डिलीट कर दिया गया। ये असंवैधानिक है।'

आप सांसद संजय सिंह ने कहा, 'हमने अपना पक्ष रखा। इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं।'

इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई थी कि उनकी राय को इसमें नहीं जोड़ा गया। मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के सदस्य संसदीय कार्य प्रणाली के तहत जो कुछ भी जोड़ना चाहते हैं, वो जोड़ सकते हैं। उनकी पार्टी को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है।'

रजत पाटीदार बने RCB के नए कप्तान, विराट कोहली ने दी बधाई

24 न्यूज अपडेट



24 न्यूज अपडेट, स्पोर्ट्स डेस्क। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने रजत पाटीदार को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। फ्रेंचाइजी ने गुरुवार को X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर इस फैसले की जानकारी दी। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि विराट कोहली फिर से कप्तान बन सकते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी ने यह जिम्मेदारी पाटीदार को सौंपी। विराट कोहली का संदेशः "आप इसके हकदार हैं" RCB ने कोहली का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा— "मैं और टीम के अन्य सदस्य आपके साथ हैं, रजत। जिस तरह से आपने इस फ्रेंचाइजी में प्रगति की है और प्रदर्शन किया है, आपने सभी RCB प्रशंसकों के दिलों में जगह बनाई है। आप इसके हकदार हैं।" 31 वर्षीय रजत पाटीदार, फाफ डु प्लेसिस की जगह लेंगे, जिन्होंने 2022 से 2024 तक टीम की कप्तानी की थी। RCB ने 2025 के लिए फाफ को रिटेन नहीं किया। पाटीदार 2021 से RCB टीम के साथ जुड़े हैं और उन्हें मेगा ऑक्शन-2024 से पहले ही रिटेन किया गया था। रजत सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2024-25 में मध्य प्रदेश के कप्तान थे और उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया। हालांकि, मुंबई ने फाइनल में मप्र को 5 विकेट से हरा दिया। पाटीदार ने उस मैच में 81 रनों की नाबाद पारी खेली थी। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 9 मैचों में 61.14 की औसत से 428 रन बनाए, जिससे वे अजिंक्य रहाणे (469 रन) के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। रजत पाटीदार को कप्तान बनाकर RCB ने युवा प्रतिभाओं को मौका देने का संकेत दिया है। अब देखना होगा कि वो IPL 2025 में अपनी टीम को कितनी सफलता दिला पाते हैं।

अडाणी ग्रीन एनर्जी श्रीलंका में नहीं बनाएगी विंड पावर कॉम्प्लेक्सः484 मेगावाट का प्रोजेक्ट 3,844 करोड़ में बनना था

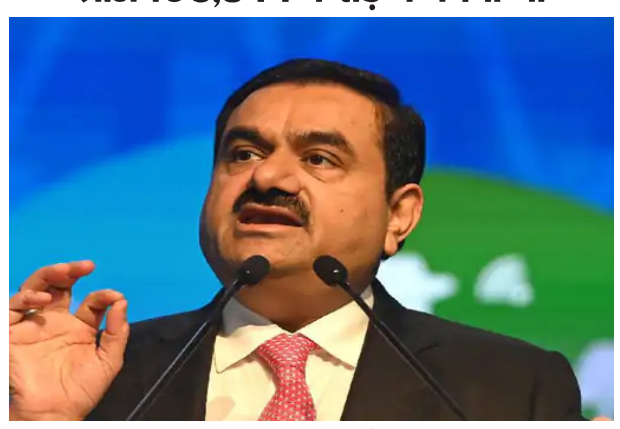

24 न्यूज अपडेट

अडाणी ग्रुप की कंपनी अडाणी ग्रीन एनर्जी अब श्रीलंका में अपने दो प्रस्तावित विंड पावर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगी। 484 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट को श्रीलंका के मन्नार और पूनरी कोस्टल एरिया में बनाया जाना था।आज यानी गुरुवार (13 फरवरी) को कंपनी ने एक प्रेस नोट के जरिए इस बात की जानकारी दी।

कंपनी ने कहा, 'अडानी ग्रीन एनर्जी ने श्रीलंका में रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी और दो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स से पीछे हटने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी श्रीलंका के संबंधित विभाग को दे दी गई है। हम श्रीलंका के लिए प्रतिबद्ध हैं और अगर श्रीलंका सरकार चाहे तो भविष्य में सहयोग के लिए तैयार हैं।'

अमेरिका में करप्शन के मामले के चलते कैंसिल किया था परचेज एग्रीमेंट

हाल ही में श्रीलंका ने अडाणी ग्रुप से पावर परचेज एग्रीमेंट खत्म करने का फैसला किया था। तब श्रीलंका ने तर्क दिया था कि ग्रुप के मालिक गौतम अडाणी पर अमेरिका में करप्शन के गंभीर आरोप लगे हैं। सरकार ने मई 2024 में अडाणी विंड पावर कॉम्प्लेक्स से बिजली खरीदने के लिए यह एग्रीमेंट किया था। श्रीलंकन सरकार इस पावर कॉम्प्लेक्स से 0.0826 डॉलर (मौजूदा वैल्यू- करीब 7.18 रुपए) प्रति किलोवाट के रेट से बिजली खरीदने के लिए समझौता किया था।

लोकसभा में पेश हुआ इनकम टैक्स बिलःइसके पन्ने 823 से घटाकर 622 किए, अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत आएंगे क्रिप्टो एसेट



24 न्यूज अपडेट

नया इनकम टैक्स बिल आज यानी गुरुवार, 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया है। 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। प्रस्तावित कानून को आयकर अधिनियम 2025 कहा जाएगा और अप्रैल 2026 में प्रभावी होने की उम्मीद है।

नए इनकम टैक्स बिल की 4 बड़ी बातें...

इनकम टैक्स बिल में असेसमेंट ईयर को टैक्स 'ईयर' से रिप्लेस किया गया है। बिल के पन्ने 823 से घटकर 622 रह गए हैं। हालांकि, चैप्टर्स की संख्या 23 ही है। सेक्शन 298 से बढ़ाकर 536 कर दिए गए हैं और शेड्यूल्स भी 14 से बढ़कर 16 हो गए है।

क्रिप्टो एसेट्स को किसी भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत गिना जाएगा, जैसे अभी नकदी, बुलियन और ज्वेलरी को शामिल किया जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी पारदर्शी और कानूनी तरीके से कंट्रोल किया जा सके।

बिल में टैक्सपेयर्स चार्टर को शामिल किया गया है, जो टैक्स पेयर्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा और टैक्स प्रशासन को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगा। यह चार्टर टैक्सपेयर्स के हितों की रक्षा करने के साथ टैक्स अधिकारियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी साफ करेगा।

सैलरी से संबंधित कटौतियां, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट को अब एक ही जगह पर लिस्ट कर दिया गया है। पुराने कानून में मौजूद मुश्किल एक्सप्लेनेशन और प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिससे टैक्सपेयर्स के लिए इसे समझना आसान हो जाएगा।



संपादकीय : खैरात के खिलाफ

किसी भी सरकार की कामयाबी इस बात से आंकी जाती है कि उसने नागरिकों के लिए काम का कैसा वातावरण बनाया और देश के आर्थिक विकास में उनका कितना योगदान सुनिश्चित किया है। मगर हमारे यहां गरीबी उन्मूलन के नाम पर चलाई जा रही खैरात की योजनाओं को उपलब्धि की तरह रेखांकित किया जाने लगा है। जब भी कोई चुनाव आता है, तो हर राजनीतिक दल बढ़-चढ़ कर मुफ्त की योजनाओं की फेहरिश्त पेश करना शुरू कर देता है। इस पर उचित ही सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने कहा कि वोट के लालच में मुफ्तखोरों और परजीवियों का एक वर्ग तैयार हो रहा है। लोगों को बिना किसी काम के मुफ्त राशन और पैसा देना सही नहीं है। सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि वह इन लोगों को मुख्यधारा में लाए, ताकि वे भी देश के विकास में योगदान दे सकें। पहले भी मुफ्त की योजनाओं को लेकर गुहार लगाई गई थी, तब अदालत ने कहा था कि चुनाव में ऐसी घोषणाओं से परहेज किया जाना चाहिए। मगर किसी भी दल ने उस नसीहत को गंभीरता से नहीं लिया। यह ठीक है कि कोई भी सरकार अपने नागरिकों को भूख से नहीं मरने दे सकती, इसीलिए भोजन का अधिकार कानून लाया गया था। मगर इसका यह अर्थ नहीं कि देश की एक बड़ी आबादी को इस तरह मुफ्तखोर और अकर्मण्य बना दिया जाए। यह व्यवस्था तभी होनी चाहिए, जब लोगों को काम न मिल सके। हर परिवार को काम देने की गारंटी के साथ मनरेगा कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें कम से कम सौ दिन का काम देने की गारंटी दी गई थी। मगर उस कार्यक्रम की स्थिति यह है कि हर वर्ष उसमें पंजीकृत लोगों की कटौती हो रही है। धन का आबंटन और काम के दिन घटते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अब वर्ष में पचास दिन काम भी मुश्किल से मिल पाता है। ऐसी स्थिति में सरकारें किसानों, महिलाओं आदि को हर महीने नगदी हस्तांतरण करने के वादे कर रही हैं। जबकि हकीकत यह है कि अस्सी करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन, महिलाओं और किसानों को नगदी हस्तांतरण, बिजली-पानी मुफ्त देने जैसी योजनाओं के कारण कई राज्य सरकारों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता गया है। जाहिर है, इससे देश की तरक्की की कोई अच्छी सूरत नहीं बनती। यह स्वाभाविक है कि जब लोगों को मुफ्त का राशन और नगदी मिलेगी, तो वे शारीरिक श्रम करने से बचेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की चिंता वाजिब है कि देश की बड़ी आबादी को खैरात की योजनाओं से अकर्मण्य बना देना देश के विकास में रोड़े अटकाने जैसा है अब धीरे-धीरे लोगों में यह मानसिकता बनती गई लगती है कि वे मुफ्त की योजनाओं को अपना अधिकार समझने लगे हैं और चुनावों के दौरान नजर टिकाए रहते हैं कि कौन-सा दल क्या क्या और कितनी मुफ्त की योजनाएं देने का वादा करता है। यह मानसिकता ज्यादा खतरनाक है। किसी भी देश का विकास अपने नागरिकों को खैरात पर जीवन जीने को प्रोत्साहित करके संभव ही नहीं हो सकता। योजनाएं ऐसी बननी चाहिए, जिनसे लोगों को काम के अवसर पैदा हों, वे कमा कर खाएं और स्वाभिमान के साथ जीवन जी सकें। उचित तो यह होगा कि सभी राजनीतिक दल तय करें कि चुनाव मुद्दों पर लड़ेंगे और खैरात की योजनाएं सिर्फ उन लोगों के लिए बनेंगी, जो बहुत जरूरतमंद होंगे।

निष्पक्षता पर सवाल

भारत निर्वाचन आयोग लगातार विवादों में है। वर्षों में उसकी निष्पक्षता पर पिछले कुछ अनेक बार सवाल उठे हैं। जिस प्रकार के आरोप उस पर लगते रहे हैं, वह देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। आयोग ईवीएम से जुड़ीं शिकायतें आज तक दूर नहीं कर सका है। गौरतलब है कि वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगली अठारह फरवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अब नई नियुक्ति केंद्र की ओर से वर्ष 2023 में लाए गए नए कानून के तहत हो सकती है। इस पर भी सवाल उठे हैं। इस मुद्दे पर शीर्ष न्यायालय का कड़ा रुख दिख रहा है। उसने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस बीच कुछ भी घटित होता है तो उसके परिणाम अवश्य भुगतने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष की स्वतंत्र समिति करे, पर सरकार ने समिति से प्रधान न्यायाधीश को हटा दिया और उनकी जगह किसी मंत्री को सदस्य बना दिया। यह चुनावी लोकतंत्र के विरुद्ध माना गया। अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र की इच्छा पर निर्भर हो गई है। विरोध इसी बात का है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से नागरिकों का जिस तरह भरोसा कमजोर हुआ है, वह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। दागी नेता आज भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आयोग उन्हें रोक नहीं पा रहा। वहीं आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई में उसकी निष्पक्षता संदिग्ध दिखती है। मतदाता सूची में गड़बड़ी के भी गंभीर आरोप हैं। वह चाहे जितनी दलीलें दे, लेकिन हकीकत है कि कई राजनीतिक दल और मतदाता ईवीएम से संतुष्ट नहीं हैं। आयोग ईवीएम में संग्रहीत आंकड़े बताने तक से इनकार करता रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा है कि ईवीएम में संग्रहीत आंकड़ों को न हटाया जाए। दरअसल, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने याचिका दायर की है कि जली हुई ईवीएम की 'मेमोरी' और 'माइक्रोकंट्रोलर' को इंजीनियर से सत्यापित किया जाए कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई है। मगर यहां सवाल सत्यापन से अधिक संदेह का है। आरोपों से घिरे आयोग को जवाब देना ही होगा।

यूडीटैक्स की गाज : तेली समाज की वाटिका सीज, 32 लाख 99,596 का यूडी टेक्स बकाया, भगवती गोल्ड ट्रांसपोर्ट पर भी लगे ताले



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. उदयपुर। नगर निगम द्वारा लगातार यूडी टैक्स वसूली को लेकर सख्त कार्रवाई लगातार जारी है, एक बार फिर से राजस्व शाखा द्वारा दो प्रतिष्ठानों को सीज किया गया। नगर निगम राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर ने बताया कि आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर नगरीय विकास कर वसूलने को लेकर फिर बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 संपत्तियों को सीज किया गया। बुधवार को ब्रह्मपोल हरिदास जी की मगरी स्थित केटीएस गार्डन, कचेली तेली समाज की वाटिका जिसका नगरीय विकास कर कुल 32 लाख 99,596/- बकाया था जिसे सीज किया गया। सबसिटी सेन्टर ब्लॉक स्थित भगवती गोल्ड ट्रान्सपोर्ट कंपनी की संपत्ति जिसका 7,65,299/- रुपए का नगरीय विकास कर बकाया था जिसे भी सीज किया गया। इनके द्वारा नगरीय विकास कर की राशि जमा नहीं कराने से नगर निगम द्वारा इन व्यावसायिक सम्पतियों पर ताला लगा इनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ बन्द करा दी गई। निगम ने नोटिस में अंकित किया की नगरीय विकास एंव स्वायत शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5513 दिनांक 29.00.2007 एंव अधिसूचना क्रमांक 8884 व 9356 दिनांक 24.08.2016 के तहत के वर्ष 2007 से 2023 तक उक्त संपत्ति का नगरीय विकास कर की पूरी रकम बकाया है। संबंधित फर्मों द्वारा टैक्स बकाया रहने के लिए कोई संतोषप्रद का कारण भी नही बताया गया है। फर्म से कुल बकाया का नोटिस भी तामिल करवाया जा चुका था। सभी कार्यवाही पूरी करने के उपरांत निगम ने कार्यवाही करते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा की उपबंधों के अधिन यू डी टैक्स की वसूली की पूर्ती हेतु दोनों संपतियो को सीज करने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान राजस्व अधिकारी के साथ सहायक प्रशासनिक अधिकारी विनोद अग्रवाल और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। नगर निगम द्वारा यू डी टैक्स वसूली को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त राम प्रकाश ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नगरीय विकास कर सरकार द्वारा हर हाल में वसूल किया जाएगा। 1 वर्ष पश्चात राज्य सरकार द्वारा इसमें छूट प्रदान की गई है जिसका शहरवासी लाभ लें। जिसे भी अपनी संपत्ति को सीज होने से बचाना है वह जल्द से जल्द नगर निगम में अपना बकाया यूडी टैक्स जमा कराएं।

अवैध पटाखा गोदाम में भीषण आग, 14 घायल, 2 गंभीर उदयपुर रैफर, अब प्रशासन कह रहा करेंगे सख्त कार्रवाई



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. बांसवाड़ा। नेताओं और अफसरों की मिलीभगत से शहर में अवैध पटाखा गोदाम चल रहा था। अब आग लग गई व लोग गंभीर घायल हो गए तो प्रशासन कह रहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। लोग पूछ रहे हैं कि जब अवैध फैक्ट्री चल रही थी तब क्या हो गया था? कहां गई सीआईडी, खुफिया पुलिस तंत्र क्या सो रहा था???? रीको इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर रोड, बांसवाड़ा पर दोपहर 2:15 बजे एक अवैध पटाखा गोदाम में भीषण आग लग गई। पति-पत्नी और 4 बच्चे सुरक्षित बच गए जबकि 14 घायल हो गए जिसमें से 2 को उदयपुर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि रीको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक अवैध पटाखा गोदाम में भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। दोपहर 2:15 बजे इंडस्ट्रियल एरिया के एक अवैध पटाखा गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। उस समय गोदाम के अंदर पति-पत्नी और उनके 4 बच्चे मौजूद थे। जैसे ही आग लगी, वे किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आए। पटाखों के कारण लगातार विस्फोट होने लगे, जिनकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी। गोदाम के बाहर 14 लोग खड़े थे, जो धमाकों की चपेट में आकर झुलस गए। धुएं का गुबार 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया।घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। 9 दमकल वाहनों को आग बुझाने में 2 घंटे लगे। शाम 4:15 बजे आग पर काबू पा लिया गया। जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव और एसपी हर्षवर्धन अगरवाला ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया। गोदाम अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था और पटाखों के निर्माण का कोई लाइसेंस नहीं था। रीको (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम) ने कहा कि गोदाम का उपयोग पटाखा भंडारण के लिए नहीं किया जाना चाहिए था। एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।यह प्लॉट अशोक अग्रवाल नामक व्यापारी को रीको द्वारा अलॉट किया गया था। लेकिन अशोक अग्रवाल ने बिना सूचना दिए इसे पटाखा व्यापारी सोनू सिंधी को किराए पर दे दिया। दोनों ही घटना के बाद से लापता हैं। कलेक्टर के अनुसार, गोदाम में गुपचुप तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे, जो कि अवैध है। पुलिस की ओर से कहा गया कि गोदाम मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्लॉट मालिक अशोक अग्रवाल और गोदाम संचालक सोनू सिंधी पर केस दर्ज किया जाएगा। आग लगने के बाद लगातार दो बड़े धमाके हुए। दो घंटे तक रह-रहकर पटाखों के फटने की आवाजें आती रहीं। आग से बचाव के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड ने गोदाम की दीवार जेसीबी से तुड़वा दी। कोतवाली थाने के सीआई देवीलाल मीणा ने दीवार तोड़ने के बाद खुद अंदर जाकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने फायर ब्रिगेड के पाइप से आग बुझाने में मदद की। इस दौरान एक और बड़ा धमाका हुआ, जिससे पुलिसकर्मी और दमकलकर्मी तेजी से बाहर भागे।

कचरा उठाने वालों का पावर जोरदार!!!

नंबर प्लेट की जरूरत नहीं, रास्ते में जहां चाहो...



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज. उदयपुर। नजारा उदयपुर के आलोक स्कूल सेक्टर 11 के पास का है। इसमें नगर निगम का कचरा उठाने वाला एक वाहन लगातार भागे जा रहा है। वाहन में कचरा उपर तक भरा हुआ है और रास्ते में जगह जगह पर गिर रहा है। खास बात यह है कि इसका कोई नंबर नहीं है। शायद इसलिए नहीं क्योंकि नंबर प्लेट से पता चल जाता है कि वाहन कौनसा है, उसका रिजस्ट्रेशन, इंश्योरेंस आदि हैं भी या नहीं। ऐसे वाहन सरपट भागते शहर के सभी चौराहों से गुजरते हैं लेकिन ठेकेदार की ऐसी सेटिंग है कि ना तो नगर निगम के अधिकारी कार्रवाई करते हैं ना ट्रेफिक पुलिस इनका चालान बनाती है। अगर काई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। बिना नंबर प्लेट के सरपट भागने की ऐसी कोई सुविधा उन शहरवासियों के पास नहीं है जिनके टेक्स के पैसों से ये वाहन चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही मारपीट के मामले के बाद कचरा वाहन के ठेकेदार पर कई गंभीर सवाल उठे थे, उनके जवाब मिलना भी बाकी है। सवाल यह उठ रहा है कि ठेकेदार को आखिर किस राजनेता या अधिकारी की शह है कि उसके हौसले नियमों को लगातार तोड़ते हुए भी बुलंद हो रहे हैं।

नाथद्वारा में श्रीनाथजी मंदिर की होली का डंडारोपण, फाग उत्सव का हुआ शुभारंभ



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. नाथद्वारा। पुष्टिमार्ग की प्रधानपीठ श्रीनाथजी मंदिर, नाथद्वारा में परंपरागत रूप से होली का डंडा रोपण किया गया। इसके साथ ही मंदिर परिसर में फाग उत्सव का शुभारंभ हो गया। बुधवार देर शाम होली मंगरा स्थित होलिका दहन स्थल पर विशेष पूजा-अर्चना के पश्चात यह विधि संपन्न हुई। इस अवसर पर भक्तों ने उल्लासपूर्वक कीर्तन और होली की धमाल में भाग लिया। साथ ही, माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रीजी प्रभु का विशेष अलौकिक श्रृंगार भी किया गया, जिसने भक्तों को दिव्य आनंद की अनुभूति कराई। श्रीनाथजी मंदिर की परंपरा के अनुसार, मुख्य प्रवेश द्वार से होली का डंडा उठाकर सेवकगण कीर्तन करते हुए नगर में शोभायात्रा के रूप में मंदिर मार्ग, लाल बाजार, केशव कॉम्प्लेक्स, फौज मोहल्ला होते हुए होली मंगरा पहुंचे। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर बंदूकों की सलामी देकर इस शुभ अवसर का सम्मान किया गया। नाथद्वारा की यह विशाल होली मेवाड़ की सबसे बड़ी होली मानी जाती है, जिसे 108 कांटों की गठरियों से तैयार किया जाता है। यह संरचना लगभग दो मंजिला भवन जितनी ऊंची होती है और इसके निर्माण में एक माह का समय लगता है। इस अवसर पर खर्च भंडार के भंडारी, मंदिर के पंड्या परेश नागर, परछना मुखिया, मशालची एवं अन्य वरिष्ठ सेवक उपस्थित रहे। होली का डांडाः परंपरा, महत्व और धार्मिक मान्यता होली का रंगों से भरा उत्सव केवल एक दिन तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसकी तैयारियां हफ्तों पहले से शुरू हो जाती हैं। इन्हीं तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है होली का डांडा रोपने की परंपरा। हालांकि यह परंपरा शहरों में धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है, लेकिन गांवों और कस्बों में आज भी इसे पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाया जाता है। होली का डांडा होलिका दहन की शुरुआती प्रक्रिया का प्रतीक है। इसे भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका की कथा से जोड़ा जाता है। गांवों और कस्बों में किसी प्रमुख स्थानकृ जैसे चौक, चौराहा या मंदिर परिसरकृपर दो डांडे रोपे जाते हैं, जो आमतौर पर सेम के पौधे से बनाए जाते हैं। यह डांडा सुरक्षित रखा जाता है, जो सत्कर्म, भक्ति और विजय का प्रतीक होता है। इसे होली की अग्नि में भस्म कर दिया जाता है, जो अधर्म और अन्याय के अंत को दर्शाता है।

दो खिलाड़ियों का राजस्थान राज्य सीनियर कबड्डी टीम में चयन



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. उदयपुर। जोधपुर में संपन्न हुई राजस्थान राज्य सीनियर पुरुष एवं महिला कबड्डी प्रतियोगिता के आधार पर उदयपुर के दो खिलाड़ियों का राजस्थान राज्य सीनियर कबड्डी टीम में चयन किया गया है । यह जानकारी देते हुए जिला कबड्डी संघ उदयपुर के आयोजन सचिव जालमचंद जैन ने बताया कि राजस्थान पुरुष टीम में उदयपुर के नरेंद्र गुर्जर एवं राजस्थान महिला टीम में उदयपुर की मनीषा अहीर का राजस्थान राज्य सीनियर कबड्डी टीम में चयन किया गया। जैन ने बताया कि राष्ट्रीय सीनियर पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 22 से 25 फरवरी तक कटक , उड़ीसा में आयोजित होगा । वहीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता दिनांक 15 से 18 फरवरी 2025 तक करनाल , हरियाणा में आयोजित होगी। नरेन्द्र एवं मनीषा का राजस्थान टीम में चयन होने पर उदयपुर जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खनूजा, उदयपुर जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष विनोद साहू, उदयपुर जिला कबड्डी संघ के सचिव मुकेश जैन , चयन समिति के सत्यनारायण सिंह गहलोत , उदयपुर जिला ओलंपिक संघ के चेयरमैन दिनेश श्रीमाली ने खुशी व्यक्त करते हुए दोनों खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाये दी है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना : अब विवाह तिथि से 1 वर्ष तक कर सकेंगे आवेदन

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 13 फरवरी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान (सहयोग एवं उपहार) योजना के तहत विवाह सहायता अनुदान के लिए आवेदन की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उदयपुर के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी विवाह तिथि से 1 वर्ष पूर्ण होने तक ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते है। पात्र आवेदक को ऑनलाइन आवेदन कर आवेदन को संबंधित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मे नियमानुसार जमा करना अनिवार्य होगा।

नेताजी हैं तो मुमकिन है,पूरा सिस्टम दंडवत,गुमनाम शिकायत पर उड़ता चार्टर्ड प्लेन वापस बुला लिया???



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. मुंबई। यह खबर पढ़कर अपना भ्रम दूर कर लीजिए कि देश में सबके साथ समान बर्ताव होता है। लोग छोटी मोटी एप्लीकेशन लेकर पुलिस थानो के चप्पलें घिसते हैं उनके काम बरसों तक नहीं होते। लेकिन यहां तो एक गुमनाम शिकायत पर चार्टर्ड प्लेन वापस बुला लिया। कार्रवाई ऐसी हुई जैसे कोई फिल्म चल रही हो। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री के बेटे ऋषिराज सावंत की बैंकॉक ट्रिप और हाई-वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत के बेटे ऋषिराज सावंत की चार्टर्ड प्लेन से बैंकॉक यात्रा एक हाई-वोल्टेज ड्रामा में बदल गई। बिना परिवार को बताए विदेश यात्रा पर निकले ऋषिराज को मध्य रास्ते से वापस बुला लिया गया, क्योंकि पुलिस को एक अनजान शख्स ने उनके अपहरण की झूठी सूचना दी थी। ऋषिराज सावंत ने बैंकॉक जाने के लिए एक चार्टर्ड प्लेन बुक किया। इस विमान में 18 सीटों की क्षमता थी, लेकिन इसमें केवल 3 लोग सवार थे। ऋषिराज और उनके दो दोस्त। इस ट्रिप पर उन्होंने कुल 68 लाख रुपए खर्च किए। 10 फरवरी को शाम 4:30 बजे उनकी फ्लाइट पुणे एयरपोर्ट से बैंकॉक के लिए रवाना हुई। इस ट्रिप के बारे में उन्होंने अपने परिवार को नहीं बताया था। उनके पिता तानाजी सावंत इस यात्रा के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने परिवार से इसे बिजनेस ट्रिप बताकर छुपाया। जब उनके परिवार को उनकी यात्रा के बारे में पता चला तो वे चिंतित हो गए। इसी दौरान पुलिस को किसी अनजान शख्स ने फोन कर दावा किया कि ऋषिराज का अपहरण हो गया है। पुलिस ने बिना देरी किए किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया और इसकी जानकारी उनके पिता तानाजी सावंत को दी। घबराए तानाजी सावंत पुणे पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे और अपने बेटे को तुरंत खोजने के लिए कहा। जब यह सूचना विमानन मंत्रालय और डीजीसीए को मिली, तो उन्होंने फ्लाइट को तुरंत वापस बुलाने का फैसला किया। उस समय यह पोर्ट ब्लेयर के पास उड़ रही थी। पायलटों को संदेश मिला कि फ्लाइट को तुरंत पुणे लौटना है। पहले पायलटों को लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन जब उन्हें आधिकारिक आदेश मिला, तो उन्होंने फ्लाइट का रूट बदल दिया। फ्लाइट में बैठे ऋषिराज और उनके दोस्त इस बात से अनजान थे कि वे बैंकॉक नहीं जा रहे, बल्कि पुणे लौट रहे हैं। नेविगेशन मैप को पहले ही बंद कर दिया गया था, ताकि वे यह न देख सकें कि दिशा बदल दी गई है।

फ्लाइट वापस पुणे पहुंची

रात 9 बजे फ्लाइट पुणे एयरपोर्ट पर उतरी। जैसे ही ऋषिराज और उनके दोस्त उतरे, वे हैरान रह गए और पायलटों से नाराजगी जताई। पायलटों ने सिर्फ इतना कहा कि वे निर्देशों का पालन कर रहे थे। इसके बाद जवानों ने फ्लाइट के अंदर जाकर तीनों को बाहर निकाला। जब पुलिस ने ऋषिराज से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने यह यात्रा छुपाई थी, क्योंकि उनके पिता गुस्सा हो जाते। उन्होंने कहा कि इसलिए उन्होंने इसे बिजनेस ट्रिप बताकर परिवार को नहीं बताया। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना उचित जांच किए ही फर्जी किडनैपिंग केस दर्ज कर लिया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि तानाजी सावंत ने अपने बेटे को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग किया। क्या पुलिस ने सिर्फ उनके प्रभाव के कारण बिना सबूतों के केस दर्ज कर लिया? इतनी महंगी चार्टर्ड फ्लाइट क्यों बुक की गई? विपक्ष ने सवाल उठाए कि ऋषिराज सावंत ने 68 लाख रुपये खर्च कर चार्टर्ड फ्लाइट क्यों बुक की? क्या यह कोई बड़ा बिजनेस डील था या सिर्फ एक फन ट्रिप? पुलिस ने बिना पूरी जांच किए किडनैपिंग का केस कैसे दर्ज कर लिया? कौन था वह अनजान व्यक्ति जिसने पुलिस को किडनैपिंग की झूठी सूचना दी? क्या तानाजी सावंत ने प्रशासन पर दबाव डालकर अपने बेटे को वापस बुलवाया? इस घटना ने महाराष्ट्र की राजनीति और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

सामूहिक विवाह में सरकार दे रही प्रति जोड़ा 25 हजार रुपए, कम से कम 10 जोड़े होना जरूरी



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान सरकार की ओर से विवाह में अपव्यय को कम करने एवं सामूहिक विवाह के आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 संचालित की जा रही है। योजना के तहत प्रति जोड़ा कुल 25 हजार रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। इस योजना का एक उद्देश्य बाल विवाह रोकना भी है। उन्होंने बताया कि इस योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह का तात्पर्य एक ही स्थान पर कम से कम 10 एवं अधिकतम 500 जोड़ों का विवाह करने से है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अनुदान की इच्छुक संस्था की ओर से ऐसे आयोजन के कम से कम 15 दिवस पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। इसके लिए राजस्थान संस्था एक्ट, 1958 अथवा सोसायटी रजि. एक्ट 1860 आदि में पंजीकृत संस्था की ओर से आधार नम्बर से राजस्थान सिंगल साइन ऑन आईडी एसएसओ पर जाकर आवेदन किया सकता है। इस योजना में वर एवं वधु में से किसी एक का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। इसके साक्ष्य संबंधित दस्तावेज लगाने होंगे। वर-वधु के आयु प्रमाण- पत्र, फोटो पहचान-पत्र, वधु की खाता पासबुक, वधु के बैंक खाते से लिंक जनाधार कार्ड की फोटो प्रति आदि आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने जरूरी है। विवाह आयोजन के 60 दिवस के भीतर विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर संस्था को प्रति जोड़ा 4 हजार व प्रत्येक वधु को 21 हजार रुपए का अनुदान प्रदान किया जाता है।

दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना से मिलेगा 50 लाख रुपए तक उपचार



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. जयपुर। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक एवं बालिकाओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना को संपूर्ण राजस्थान राज्य में शुरू किया है। दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों के इलाज में सरकार सहयोगी बनेगी। ऐसे बच्चों को चिन्हिकृत कर सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके परिवारों को पात्रतानुसार निरन्तर आर्थिक सहायता दी जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार सरकार ने 58 तरह की बीमारियों को दुर्लभ माना है। योजना से लाभान्वित करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, वहीं विभाग की ओर से ऐसे बच्चों को चिन्हीकरण किया जा रहा है।

हर माह मिलेगी सहायता

दुर्लभ बीमारियों से पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन दुर्लभ बीमारी निधि का गठन किया जाएगा। इस निधि में राज्य सरकार से अनुदान के अलावा क्राउड फंडिंग, भामाशाहों व सीएसआर से प्राप्त राशि को जमा कर पीड़ितों की सहायता की जाएगी। आवेदन के आधार पर सभी तथ्य सही व पाए जाने पर प्रक्रिया के तहत पीड़ित को प्रति माह 5000 रुपए की राशि दी जाएगी। पीड़ित का 50 लाख रुपए तक उपचार करवाया जाएगा। योजना के तहत दुर्लभ बीमारी के प्रमाणन के लिए केन्द्र व राज्य की ओर से घोषित चिकित्सा संस्थाओं के सक्षम अधिकारी अधिकृत होंगे।

ये हो सकेंगे लाभान्वित

दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चे जो 18 वर्ष से कम आयु, राजस्थान के मूल निवासी हो, लाभान्वित हो सकेंगें। योजनान्तर्गत सक्षम चिकित्सा अधिकारी की ओर से दुर्लभबीमारी से पीड़ित होने का प्रमाण पत्र जरूरी होगा। बीमारी का उपचार होने पर सहायता बंद हो जाएगी। पालनकर्ता, बालक या बालिका के दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में जनाधार नम्बर से ई-मित्र अथवा स्वयं की एसएसओ आईडी से बायोमेट्रिक या ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। सरकार ने दुर्लभ बीमारियों को सूचीबद्ध किया। विभाग की ओर से भी चिकित्सा विभाग के माध्यम से सम्पर्क कर इस तरह के बच्चों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है।

महाकुंभ मेला हेतु साबरमती-बनारस-साबरमती मेला स्पेशल रेलसेवा की संचालन अवधि में 01 ट्रिप का विस्तार



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, जयपुर। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु महाकुंभ मेला-2025 के लिए साबरमती-बनारस-साबरमती महाकुंभ मेला स्पेशल रेलसेवा की संचालन अवधि में 01 अतिरिक्त ट्रिप का विस्तार किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाडी संख्या 09453, साबरमती-बनारस महाकुंभ मेला स्पेशल रेलसेवा दिनांक 22.02.25 को (01 ट्रिप) साबरमती से 11.00 बजे रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर 23.10 बजे आगमन व 23.20 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 16.00 बजे बनारस पहुँचेगी। इसी प्रकार गाडी संख्या 09454, बनारस-साबरमती महाकुंभ मेला स्पेशल रेलसेवा दिनांक 23.02.25 को (01 ट्रिप) बनारस से 19.30 बजे रवाना होकर अगले दिन जयपुर स्टेशन पर 13.15 बजे आगमन व 13.20 बजे प्रस्थान कर दिनांक 25.02.25 को 00.30 बजे साबरमती पहुँचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, पिंडवाडा, फालना, रानी, मारवाड जं., ब्यावर, अजमेर, किशनगढ, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, आगराफोर्ट, टूण्डला, इटावा, गोविन्दपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज (वाया प्रयागराज रामबाग) व ज्ञानपुर रोड स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस रेलसेवा में 01 सैकण्ड एसी, 05 थर्ड एसी, 14 द्वितीय शयनयान, 02 साधारण श्रेणी व 02 गार्ड डिब्बो सहित कुल 24 डिब्बे होगे।

राजस्थान में आया भूकंप, सिरोही-जालोर में हिली धरती:3-4 सेकेंड तक महसूस हुए झटके; घरों-दुकानों से निकलकर भागे लोग



24 न्यूज अपडेट

राजस्थान में गुरुवार शाम करीब 5:28 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। जालोर और सिरोही जिले के इलाकों में करीब 3-4 सेकेंड तक धरती कांपती रही। भूकंप की तीव्रता और केंद्र की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

सिरोही जिले के माउंट आबू, आबूरोड और रेवदर के साथ ही जालोर के रानीवाड़ा और जसवंतपुरा सहित आसपास के क्षेत्रों में झटके महसूस होते ही लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए और एक-दूसरे को फोन कर जानकारी साझा करने लगे।

फिलहाल भूकंप के झटकों से अब तक कहीं पर जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सतर्क रहने व शांति बनाए रखने की अपील की गई है।

भूकंप क्यों आता है?

हमारी धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी-छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है।

जोधपुर में रिटायर्ड XEN से 11 दिन में 60लाख ठगे:बेटे से बोले- तू समझता नहीं, इस उम्र में जेल जाना पड़ेगा; ठगों को असली सीबीआई समझ बैठे



24 न्यूज अपडेट

साइबर ठगों ने 85 साल के RSEB के रिटायर्ड XEN को 11 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके 60 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर करवा ली। साइबर ठगों ने बुजुर्ग को डराया कि उन्हें असली सीबीआई समझने लगे। बेटे को जब पूरे मामले की जानकारी लगी तो बोले- तू समझता नहीं है, सीबीआई केस हुआ है। इस उम्र में जेल जाना पड़ेगा। परिजनों की समझाइश के बाद बुजुर्ग थाने में FIR देने को राजी हुए। मामला जोधपुर के सरदारपुरा थाना इलाके के नेहरू पार्क क्षेत्र का 12 फरवरी का है। पुलिस ने FIR होने के बाद उनके खाते में बचे 5 लाख रुपए होल्ड करवाए हैं।

2 फरवरी से शुरू हुई थी ठगी

सरदारपुरा थानाधिकारी शेषकरण ने बताया- नेहरू पार्क क्षेत्र में रहने वाले अजीतराज भंडारी (85) आरएसईबी से सेवानिवृत्त हैं। वे जोधपुर में अकेले ही रहते हैं। उनका बेटा और बहू दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने बेटे के साथ आकर थाने में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया- 2 फरवरी को भंडारी के पास एक अनजान नंबर से वॉट्सएप कॉल आया। इसमें बात करने वाले शख्स ने खुद को सीबीआई का अफसर बताते हुए नरेश गोयल के जेट एयरवेज से जुड़े फ्रॉड केस में भंडारी के शामिल होने की बात कही। ऐसे में पूछताछ और अन्य जानकारी के लिए उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया।

11 दिन में 60 लाख ठगे

रिपोर्ट में बताया कि इसके बाद शुरू हुए कॉल्स में एक शख्स खुद को पुलिस अधिकारी बता खातों में जमा रुपयों के बारे में जानकारी लेने लगा। अगले दिन से अज्ञात शातिरों ने बुजुर्ग को खातों में जमा राशि को जांच पूरी होने तक उनके बताए अन्य खातों में ट्रांसफर करने को कहते रहे। ऐसा नहीं करने पर गिरफ्तारी का भय दिखाने लगे। बुजुर्ग बदमाशों के झांसे में आ गए और उनके बताए अनुसार अलग-अलग खातों में कुल 60 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए।

गहलोत बोले- मेरे वक्त भी फोन टैपिंग के आरोप लगे:मैंने सदन में जवाब दिया था, सीएम भजनलाल को मेरी तरह कहने का भाव क्यों नहीं आया



24 न्यूज अपडेट

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोपों और बीजेपी की तरफ से उन्हें नोटिस देने के मामले में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि विपक्ष सदन में सरकार से मांग कर रहा था कि वास्तविकता क्या है। मेरे वक्त में भी फोन टैपिंग के आरोप लगे थे। मैंने खुद हाउस में खड़े होकर कहा था कि किसी भी सांसद विधायक का टेलीफोन न टैप हुआ है, न हो रहा है, ना आगे होगा। अगर टैप नहीं हो रहा है तो मेरी तरह सीएम भजनलाल भी गृह मंत्री हैं। सदन के नेता हैं। उनको मेरी तरह बात करने का भाव क्यों नहीं आया। गहलोत ने कहा- क्यों नहीं उन्होंने सदन में कहा कि किरोड़ी लाल मीणा का फोन टैप नहीं किया गया। बात खत्म हो जाती। विपक्ष के लोग भी सहयोग करते। बहस होती।

कुछ लोग हवा में आरोप लगा देते हैं, बेढम बाहर बोल रहे थे सदन में क्यों नहीं बोले

गहलोत ने कहा- कुछ लोग हवा में आरोप लगा देते हैं। इस केस में किरोड़ी लाल मीणा का क्या हुआ है। अगर आउट ऑफ वे जाकर टेलीफोन टैप किया है तो सरकार ने क्राइम किया है। इसको स्पष्ट कौन करेगा? विधानसभा के बाहर आकर गृह राज्य मंत्री बेढम बोल रहे हैं , वो सदन के अंदर क्यों नहीं बोले। इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए।

टेलीफोन टैप करने की परंपरा राजस्थान में नहीं

गहलोत ने कहा- टेलीफोन टैप करने की परंपरा राजस्थान में नहीं है। कानून किसी का टेलीफोन टैप करने की अनुमति नहीं देता। जब तक कोई असामाजिक तत्व नहीं हो। किसी पर शक बना हुआ है की कोई राजद्रोह का काम कर रहा है। उसके फोन जरूर गृह मंत्रालय की अनुमति से टैप करने का काम होता है। कोई भी अधिकारी टेलीफोन टैप नहीं कर सकता है। होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है। उसका पूरा प्रोसेस बना हुआ है।

कार्यालय में विलम्ब से आने वाले एवं बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरुद्ध होगी कार्रवाई

24 न्यूज अपडेट

जयपुर, 13 फरवरी। प्रदेश के राजकीय कार्यालयों में विलम्ब से आने वाले एवं बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश हैं कि सरकारी कार्यालय में आने वाले आमजन के कार्य जल्द से जल्द हों, उन्हें इसमें कोई असुविधा न हो, इसके लिए सरकारी कार्मिक निर्धारित समय पर अपनी सीट पर बैठें, समस्याओं का समाधान करें, आमजन को सरकारी योजनाओं के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दें। इस निर्देश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने विभिन्न टीमों का गठन किया है जो निरन्तर कार्यालयों में जाकर फीडबैक ले रही है। विभाग की शासन सचिव श्रीमती उर्मिला राजोरिया ने बताया कि उप शासन सचिव श्री महेन्द्र परेवा के नेतृत्व में विभागीय दल द्वारा गुरूवार को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के विभिन्न राजकीय कार्यालयों एवं विभागों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 92 उपस्थिति पंजिकाओं को जब्त किया गया। इनमें 21.42 प्रतिशत राजपत्रित और 13.45 प्रतिशत अराजपत्रित कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए कार्मिकों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस राज्य स्तरीय निरीक्षण दल में अनुभागाधिकारी श्री महेन्द्र कुमार सरावता, सहायक अनुभागाधिकारी श्री चेना राम भदाला और दयाराम गुर्जर शामिल रहे।

30 हजार की रिश्वत लेते असिस्टेंट इंजीनियर समेत 2 गिरफ्तार:एसीबी की कार्रवाई; कॉमर्शियल कनेक्शन देने की एवज में मांगे थे एक लाख



24 न्यूज अपडेट

भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बिजली विभाग के दो इंजीनियर को 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया हैं।

एसीबी के डिप्टी एसपी पारसमल ने बताया- परिवादी उदय लाल ने एक रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया कि उसकी एमपीआईएल ऑयल मिल के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस जारी करने और उसकी फाइल को हायर ऑफिसर तक भिजवाने के एवज में उससे एक लाख रुपए की रिश्वत राशि मांगी जा रही है।

शिकायत के सत्यापन के दौरान पीड़ित को 20 हजार रुपए देकर भेजा गया, जिसे दोनों सहायक इंजीनियर द्वारा ले लिया गया। आज शिकायत सत्यापन के बाद टीम ने 30 हजार की राशि देकर परिवादी उदयलाल को भेजा। यहां बनेड़ा एवीएनएल में कार्यरत एईएन मुकेश(37) पिता सुंदरलाल बेरवा निवासी दौसा और कॉमर्शियल असिस्टेंट विनोद कुमार(28) पिता पोखरमल रैगर निवासी डीडवाना प्रथम को गिरफ्तार किया है।

विद्युत निगम ने उपभोक्ताओं को लगाई करोड़ों की चपत, वसूली के खिलाफ ज्ञापन



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, उदयपुर। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के साथ अजमेर विद्युत निगम द्वारा बेस फ्यूल सरचार्ज के नाम पर अन्यायपूर्ण वसूली की जा रही है। तिमाही फ्यूल सरचार्ज निर्धारण के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर 2024 के लिए 9 पैसे प्रति यूनिट दर तय की गई थी। लेकिन 57 पैसे प्रति यूनिट की दर से बेस फ्यूल सरचार्ज वसूल कर लिया गया। उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 48 पैसे प्रति यूनिट समायोजित किया जाना था, जो नहीं किया गया। यह वसूली मामूली नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में कुल 1319 करोड़ रुपये की बनती है। अतिरिक्त वसूली गई राशि को अगले महीने के बिल में समायोजित किया जाना चाहिए, लेकिन निगम द्वारा ऐसा नहीं किया गया।इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संगठन ने इस मुद्दे को उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अतिरिक्त जिला कलेक्टर उदयपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। मांग की गई कि उपभोक्ताओं को अधिक वसूली गई राशि का शीघ्र समायोजन कर राहत प्रदान की जाए। प्रतिनिधिमंडल में प्रांत संगठन मंत्री राकेश पालीवाल, जिला अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा, महिला अध्यक्ष पूर्णिमा बोकड़िया, मंत्री हरी देवी, सदस्य हरिशंकर तिवारी, फतहलाल पारिक, विष्णुशंकर जोशी, सूर्यप्रकाश पालीवाल, राजेंद्र स्वर्णकार, गोवर्धन वीरवार, संगीता जैन, नीलू शर्मा आदि शामिल थे। बताया गया कि विद्युत निगम की यह अतिरिक्त वसूली उपभोक्ताओं के साथ आर्थिक अन्याय है। सरकार को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर, वसूली गई अतिरिक्त राशि को समायोजित कराना चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।

बेणेश्वर धाम के त्रिवेणी संगम पर उमड़ी भक्तों की भीड़:मंदिरों में दर्शन के साथ मेले में जमकर खरीदारी, झूलों का लिया आनंद



24 न्यूज अपडेट

राजस्थान के बेणेश्वर धाम में सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर चल रहे पांच दिवसीय मेले का तीसरा दिन उत्साह से मनाया गया। गुरुवार की सुबह मंहत अच्युतानंद महाराज द्वारा हरि मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने पितरों का तर्पण-अर्पण कर आत्मा की शांति की कामना की। मेला घाट पर पूजा के उपरांत भक्तों ने राधा कृष्ण मंदिर, शिवालय, ब्रह्माजी मंदिर और वाल्मिकी मंदिर के दर्शन किए। दर्शन के लिए सुबह से ही महिलाओं और पुरुषों की अलग-अलग कतारें लगी रहीं। मेले में एक हजार से अधिक छोटी-बड़ी दुकानें सजी हैं, जहां लोग कपड़े, बर्तन, गृहस्थी के सामान, कृषि उपकरण और सौंदर्य प्रसाधनों की खरीदारी कर रहे हैं। मनोरंजन के लिए बड़ा झूला, नाव झूला और टॉय ट्रेन की सवारी का विशेष आकर्षण है।

विशेष चिंता का विषय यह है कि धारा 144 के तहत शस्त्रों की बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद मेले में 6-7 दुकानों पर तलवार, भाला जैसे शस्त्रों की खुलेआम बिक्री हो रही है। प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

चेतक चौराहे पर पशु कल्याण व जागरूकता संबंधी लिफलेट का वितरण



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 13 फरवरी। पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान की ओर से पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरूकता माह के तहत गुरुवार को शहर के चेतक चौराहे पर पशुकल्याण संबंधी लिफलेट का वितरण किया गया। पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान के उपनिदेशक डॉ. सुरेन्द्र छंगाणी ने कहा कि पशुओं का उपयोग केवल निजी स्वार्थ के लिये करना, उपयोगिता समाप्त होने के पश्चात् उसे लाचार छोड़ देना पशुक्रूरता अधिनियम 1960 के तहत दण्डनीय अपराध है। पशुपालन डिप्लोमा के विद्यार्थियों ने इस आशय के लिफलेट चेटक चौराहे पर वितरित कर आमजन से पशुओं के प्रति दयाभाव रखने का आह्वान किया। डॉ. पद्मा मील व डॉ. ओमप्रकाश साहु ने भी कार्यक्रम में सहयोग दिया।

विधायक डांगी ने किया लेक्रोज प्रतिभाओं का अभिनंदन



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 13 फरवरी। ओलम्पिक खेल लेक्रोज की राष्ट्रीय सीनियर प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों का विधायक उदयलाल डांगी ने सम्मान कर बधाई दी। लेक्रोज फेडरेशन ऑफ इंडिया राजस्थान व राजस्थान लेक्रोज संघ की मेजबानी में उदयपुर में आयोजित हुई राष्ट्रीय सीनियर लेक्रोज प्रतियोगिता की स्वर्ण पदक विजेता राजस्थान टीम में सम्मिलित विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर के खिलाड़ी एशियाई रजत पदक विजेता व प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ स्कोरर सालेडा ग्राम की जुला कुमारी गुर्जर, मुकन कुमारी गुर्जर, मेनार के पीयूष मेनारिया तथा प्रशिक्षक नीरज बत्रा का विधायक डांगी ने अभिनंदन किया और शुभकामनाएं देते हुए उच्च उपलब्धियां हासिल कर क्षेत्र व देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही लेक्रोज खेल की उन्नति के लिए हरसंभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल सहित खेल प्रेमी उपस्थित थे।

बड़ा खेल, नेताओं को बचाया, निचले स्तर के कर्मचारियों पर गिरी गाज



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, बांसवाड़ा। हम ऐसे सिस्टम में रहे हैं जहां पर नेताओं के कहे बिना पत्ता तक नहीं हिलता । नेताओं का गठजोड़ जब जमीन माफिया से हो जाता है तब अधिकारियों पर दबाव आता है। अधिकारी खुद को बचाते हुए निचले कर्मचारियों को गडबडजाला करने पर मजबूर कर देते हैं। उसके बाद मामला सेटल हो जाता है। जब कहीं से कोई बड़ा दबाव आता है या न्यायालय का डंडा पड़ता है तब सबसे पहले निचले स्तर के कर्मचारी सस्पेंड कर दिए जाते हैं। जांच लंबित रखी जाती है और धीरे धीरे पूरा मामला सेटल कर दिया जाता है। बहरहाल अब यह दस्तूर बन चुका है। अगर ढंग से जांच हो तो सबसे पहले उपर के हाथियों पर गाज गिर जाए। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत सिंह यादव ने 5 गिरदावर और 2 पटवारी को बुधवार को सस्पेंड कर दिया है। इन सभी पर नेशनल हाईवे 927-ए के किनारे गढ़ी तहसील में 91 बीघा सरकारी जमीन को मिलीभगत कर लोगों के नाम (खातेदारी) करने का आरोप है। इसी मामले में आनंदपुरी के नायब तहसीलदार अनिल ताबियार को निलंबित करने के लिए राजस्व मंडल को पत्र लिखा है। गढ़ी तहसीलदार ने एसीबी में मामला दर्ज कराया है। डूंगरपुर जिले के चीखली पटवार मंडल के पटवारी निखिल गरासिया को डूंगरपुर कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। सेवानिवृत्त तहसीलदार केसरसिंह समेत सभी आरोपी अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ गढ़ी तहसीलदार ने 12 फरवरी को एसीबी में मुकदमा दर्ज कराया है। सभी आरोपियों की ओर से खातेदारी की गई 91 बीघा जमीन को खातेदारी से वापस सरकारी नाम दर्ज कर दिया है। कलेक्टर डॉ. यादव ने बताया कि गढ़ी तहसील में वर्ष 2022 से 2023 के बीच बेड़वा, साकरिया, भगोरा और रोहिड़ा में सरकारी जमीन को मिलीभगत से लोगों के नाम कर दी। इस पर भगोरा पटवारी नीलेश परमार, आरपीजी पटवारी अभिलाषा जैन, वजवाना गिरदावर दीपक जैन, परतापुर गिरदावर गौतमलाल पाटीदार, प्रदीप सुथार, खेड़ा गिरदावर दिनेशचंद्र पाटीदार और अविनाश राठौड़ को निलंबित किया है। प्रकरण में शामिल आनंदपुरी के नायब तहसीलदार अनिल ताबियार (तत्कालीन गिरदावर गढ़ी) को निलंबित करने के लिए राजस्व मंडल को पत्र लिखा है। कलेक्टर ने पत्र में लिखा है कि यह प्रकरण गंभीर प्रवृत्ति का है। इधर, सेवानिवृत्त तहसीलदार केशरसिंह चौहान पर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। सभी कर्मचारी-अधिकारियों ने खातेदारों के साथ मिलीभगत करके षडयंत्रपूर्वक सरकारी जमीन को लोगों के नाम (खातेदारी) की।

प्रेमिका से मिलने निकले पाली के प्रॉपर्टी डीलर हत्या, कार उदयपुर के जंगलों से बरामद

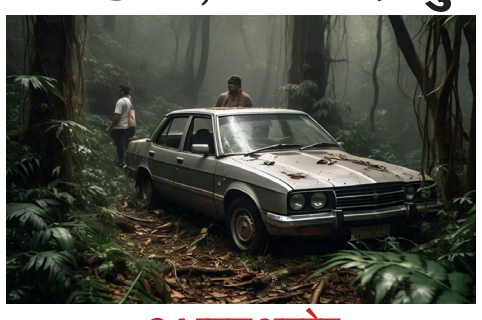

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. पाली। सुमेरपुर के पास पुराड़ा गांव से लापता हुए प्रॉपर्टी डीलर सुरेश कुमार देवासी (30) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार रात को पिंडवाड़ा-उदयपुर हाईवे के पास मोरस गांव के जंगल में उसका शव बरामद हुआ। सुरेश के सीने में गोली लगी थी और उसकी कार घटनास्थल से 40 किलोमीटर दूर उदयपुर के जंगल में मिली। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सुरेश का अफेयर एक आदिवासी युवती से था। 8 फरवरी को प्रेमिका के बुलावे पर वह कार से पुराड़ा गांव से निकला था। शक है कि लड़की के परिजनों को इस रिश्ते की भनक लग गई, जिसके बाद उन्होंने सुरेश को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए कार को उदयपुर के जंगल में छिपा दिया। पुलिस ने हत्या के संदेह में तीन लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। हत्या लूट के इरादे से हुई या ऑनर किलिंग का मामला है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पोस्टमॉर्टम के दौरान तीन गोलियों के निशान मिले और एक गोली सुरेश के सीने में फंसी मिली। यह गोली पिस्टल की थी या देसी कट्टे की, इसकी जांच जारी है। 8 फरवरी को सुबह 4:30 बजे सुरेश कार से पिंडवाड़ा के लिए निकला। 6:11 बजे उसने मोरस टोल प्लाजा पार किया, उसके बाद से उसका फोन बंद हो गया। जब दिनभर कॉल नहीं लगा, तो परिजनों ने सुमेरपुर सदर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। 13 फरवरी को मोरस पुलिस चौकी से 3 किमी दूर जंगल में शव मिला। पुलिस हत्या की सटीक वजह और हत्यारों की पहचान में जुटी है। वहीं, परिवार ने इसे लूट के इरादे से हत्या बताया है। पुलिस फॉरेंसिक जांच और हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ कर रही है।

जीजा ने साली पर किया चाकूवार, बीमार पत्नी को पीट रहा था, बीच बचाव में आई थी



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने शराब के नशे में अपनी ही साली (पत्नी की बहन) पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। यह घटना शहर के नजदीकी गांव लालजी का खेड़ा में हुई। आरोपी व्यक्ति ने अपनी बीमार पत्नी को पीट रहा था, जिसे बचाने के लिए उसकी साली बीच में आई। इसी दौरान आरोपी ने साली पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। यह मामला सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। घटना की जानकारी देते हुए पीड़िता काली देवी ने बताया कि उसका पति शंकर शराब के नशे में घर पर उसके साथ मारपीट कर रहा था। काली देवी पहले से ही बीमार चल रही थी और कई दिनों से अस्वस्थ थी। इसी वजह से उसकी बहन देवू बाई, जो मांगरोल चौराहे के पास रहती है, उससे मिलने के लिए घर आई थी। जैसे ही देवू बाई घर पहुंची, उसने देखा कि उसकी बीमार बहन काली देवी को उसका पति शंकर पीट रहा है। यह देखकर देवू बाई ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की और उसके बीच में आ गई। जब देवू बाई ने अपनी बहन काली देवी को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, तो इससे आरोपी शंकर को गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने देवू बाई के गले पर चाकू से वार कर दिया। इस हमले के बाद शंकर मौके से भाग निकला। घायल देवू बाई को उसकी बहन काली देवी ने जिला अस्पताल ले जाया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। देवू बाई की हालत गंभीर बताई जा रही है।घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। काली देवी ने पुलिस को घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी शंकर को गिरफ्तार करने के लिए तलाश जारी है।

5,500 से अधिक नर्सिंग कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: प्रमोशन का रास्ता खुला!



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, सलूंबर। आखिरकार, लंबे इंतजार के बाद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग संवर्ग के 5,500 से अधिक कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने लगभग दो साल पहले लगाई गई रोक को हटा दिया है, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जस्टिस अनूप ढंड ने सरकार की स्टे वेकेशन एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए यह रोक हटाई। हाईकोर्ट ने अपने दो अलग-अलग आदेशों, 20 अप्रैल 2023 और 27 फरवरी 2024 के तहत नर्सिंग संवर्ग की रिव्यू डीपीसी और डीपीसी पर रोक लगा दी थी। इस वजह से नर्सिंग कर्मचारियों की पिछले 7 साल की सीनियरिटी और 5 साल के प्रमोशन अटक गए थे। **कोर्ट का फैसला** - हाईकोर्ट ने रोक हटाते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ताओं के रिप्रेजेंटेशन को तीन हफ्ते में तय करें। इसके साथ ही अन्य कर्मचारियों की सीनियरिटी और प्रमोशन तय करने पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। सरकारी अधिवक्ता अर्चित बोहरा ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 2023 में 2013-14 से 2019-20 तक के कार्मिकों की रिव्यू डीपीसी और 2020-21 से 2022-23 के कार्मिकों की नियमित डीपीसी की बैठक की थी। लेकिन, लगभग 20 कर्मचारी यह कहते हुए कोर्ट चले गए कि डीपीसी में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन नहीं किया गया। उनकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 20 अप्रैल 2023 को प्रमोशन पर रोक लगा दी। वहीं, रिव्यू डीपीसी में जिन 71 कार्मिकों की सीनियरिटी क्रमांक में बदलाव हुआ, वे भी कोर्ट पहुंच गए। इस पर कोर्ट ने 27 फरवरी 2024 को सीनियरिटी प्रोसेस को भी रोक दिया। **किसे मिलेगा लाभ**? कोर्ट की रोक के बाद लगभग 5,168 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सीनियरिटी प्रोसेस पर रोक की वजह से अपने अगले प्रमोशन, जो कि नर्सिंग अधीक्षक के पद पर होना है, का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा 784 नर्सिंग ऑफिसर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। अब कोर्ट स्टे हटने के बाद इन कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता खुल गया है। 2022-23 तक के प्रमोशन होने के बाद विभाग इसके आगे के सालों के प्रमोशन भी कर सकेगा। इससे न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि विभाग में भी कार्यक्षमता और मनोबल में वृद्धि होगी।

नाम का ड्राइ स्टेट गुजरात, बॉर्डर पर तस्करों ने मचा रखी धूम, डूंगरपुर पुलिस ने सालभर में पकड़े 784 तस्कर, जो बच गए वो

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बीते सालभर में सख्त अभियान चलाया। पुलिस ने 747 से ज्यादा कार्रवाई करते हुए 784 तस्करों को गिरफ्तार किया और 64,550 बोतल अवैध शराब बरामद की। इनमें अंग्रेजी, देशी, हथकढ़ और बीयर शामिल थीं। खासकर 42,113 बोतल अंग्रेजी शराब पकड़ी गई, जिसे तस्कर गुजरात ले जाने की फिराक में थे। इससे यह साफ हो रहा है कि कितने भी सख्त कानून बना लो, तस्करों को ज्यादा फर्क नही पड़ने वाला है। पुलिस ने एक साल में साढ़े चौंसठ हजार बोतलों की तस्करी रोक दी मगर क्या इससे तस्करी रूक गई। सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि इसमें खेल बहुत उंचे स्तर तक है व पूरी मशीनरी शामिल है। गुजरात में शराब तस्करी का बढ़ता नेटवर्क गुजरात में शराब पर पाबंदी के चलते वहां अवैध शराब की मांग ज्यादा रहती है। तस्कर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और आंध्रप्रदेश से शराब लाकर गुजरात बॉर्डर पर सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर, रामसागड़ा थाना क्षेत्र, वीरपुर मेवाड़ा बॉर्डर, धंबोला और सारथुना बॉर्डर शराब तस्करी के मुख्य रूट बन चुके हैं। शराब तस्करी में इस्तेमाल होने वाले 53 वाहन जब्त किए गए, जिनमें 22 ट्रक (सबसे ज्यादा बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने पकड़े) 18 कार 4 पिकअप 2 टेंपो 7 दुपहिया वाहन हैं। पुलिस का दावा है कि तस्करों की गिरफ्तारी और जब्ती की बढ़ती संख्या ने शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया लेकिन अगर मच गया होता तो तस्करी रूक गई होती। जमीनी हालात तो ऐसे नहीं है। तस्कर शराब की तस्करी के लिए गुप्त केबिन वाले ट्रक, टैंकर और बिजली उपकरणों की आड़ में शराब लाने जैसे नए-नए तरीके आजमा रहे हैं। लेकिन पुलिस की सख्त चौकसी के चलते इनका भंडाफोड़ हो रहा है। एसपी मोनिका सेन के नेतृत्व में पुलिस अवैध शराब तस्करी को रोकने के लिए कई सफल अभियान चलाए हैं।

24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक - सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा ।